प्राधिकरण को इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के हितों की रक्षा करते हुए शर्तों के अधीन नियमों में छूट देने का निर्देश दिया था इन प्लाटों पर भवन निर्माण सम्बधी स्थिति जहां छूट प्रदान की गई है, का पता लगाया जा रहा है, जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

नई कृषि नीति

191. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई कृषि नीति बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक घोषित किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने एक उपयुक्त और लाभदायक नीति बनाने के उद्देश्य से राज्यों से सुझाव मांगे हैं ;

(घ) यदि हां, तो यह सुझाव कब मांगे गए थे और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अक्तूबर के अंत तक इस नीति के संबंध में अपने सुझाव भेज दिए थे ; और

(ङ) क्या सरकार अगली रबी फसल के बोने के समय तक नई कृषि नीति की घोषणा करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) मार्च, 1991 में तैयार किए गए कृषि नीति संबंधी संकल्प का एक प्रारूप राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और कृषि विश्वविद्यालयों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचारित किया गया था । अक्तूबर, 1991 के अन्त तक मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप प्रशासन से टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं । अन्य राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जाएगी ।

Conference of Association of Indian Universities

192. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 66th Conference of the Association of Indian Universities (AIU) held recently in Thiruvananthapuram has made several recommendations particularly concerning higher education; and

(b) if so, what are the main recommendations and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (KUMARI MAMTA BANERJEE:) (a) and (b) The Association of Indian Universities organised a National Seminar on "Decentralisation of Higher Education System" at Thiruvananthapuram on October 8, 1991. According to the information furnihsed by AIU, the Association has not finalised the proceedings of the Conference. The recommendations of the Conference would be examined by Government after they are received from AIU.

Implementation of Public Premises (Eviction) Act

193. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the implementation of the Public Pre-